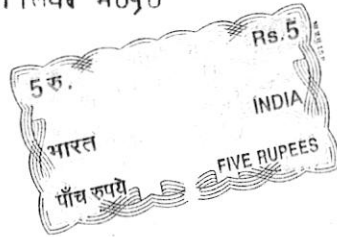
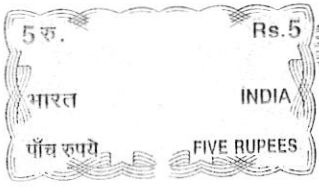


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०



1. किशोरजी शिवा १५-७/२३५९  
बुद्धसेन पटेल पिता स्व० वन्द्रभान पटेल उम्र 62 वर्ष,

2. नीरज कुमार पटेल पिता स्व०श्री रामसलोने पटेल उम्र 35 वर्ष,

3. बेवा सीतला पटेल पत्नी रामसलोने पटेल उम्र 58 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम गोरगांव 164 तह० रायपुर कचु० जिलारोवा म०प्र०  
दिनांक 26-7-17  
नगरानी कर्तागण

बनाम्  
स्व.  
कलक २०१७/१७  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

1. बाल्मीक पटेल पिता श्री वन्द्रभान पटेल उम्र वर्ष, निवासी ग्राम गोरगांव  
164 तह० रायपुर कचु० जिला रोवा म०प्र० गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी  
तहसील रायपुर कचु० जिला रोवा म०प्र० के अपील  
प्रकरण क्रमांक 16/अ27/अपील/ 2016-17 आदेश  
दिनांक 5/7/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता  
1959ई०

मान्यवर,


निगरानी का संक्षिप्त सार निम्न है:-

यहकि उक्त निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कचु०  
जिला रोवा म०प्र०के अपील प्रकरण क्र. 16/अ27/अपील/2016-17 आदेश दि०  
5/7/2017 के विरुद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा  
रही है उक्त निगरानी में महत्वपूर्ण तथ्य यह हैकि - गैरनिगरानीकर्ताविवारण  
न्यायालय में बटनवारा में विधिवत सहमत था । निगरानीकर्तागण एवं गैरनिगरानी-

*(Handwritten signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक III/निगरानी/रीवा/भू-रा0/2017/2359

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-2017	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रायपु कर्चुलियान के अंतरिम आदेश दिनांक 05-7-2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। प्रश्नाधीन आदेश में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को म्याद की धारा 5 के आवेदन पर सुनवाई कर विस्तार से आदेश पारित कर ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य नहीं पाया जिससे यह माना जा सके कि उक्त अंगूठे के निशान अनावेदक के है इसी कारण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील को अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। अनुविभागीय अधिकारी से धारा 5 के आवेदन पर विस्तार से आदेश पारित कर निराकरण किया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी अधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (एस0एस0 अली)                      सदस्य                 </p>	